

## एस.आर.बोम्मई बनाम भारत संघ मामला 1994

### प्रलिस के लयः

[अनुच्छेद 356, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, संघवाद, न्यायकऱ समीक्षा](#)

### मेन्स के लयः

एस.आर.बोम्मई बनाम भारत संघ मामले का महत्त्व, राष्ट्रपतऱशासन, अनुच्छेद 356 का अनुचतऱ उपयोग

[स्रोतः हदऱस्तान टाइम्स](#)

### चर्चा में क्यों?

एस.आर.बोम्मई बनाम भारत संघ मामले पर वर्ष 1994 में [भारत के सर्वोच्च न्यायालय](#) की नौ-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा नरऱणय कयऱ गयऱ जो [अनुच्छेद 356](#) के तहत राज्ऱ सरकारों की मनमाना रूप से बरखास्तगी को प्रतऱबधतऱ करता है। इस नरऱणय के 30 वर्ष बाद भी भारत के संवैधानकऱ ढाँचे को आकार देने में इसकी भूमकऱ बनी हुई है।

### एस.आर.बोम्मई बनाम भारत संघ मामला क्ऱ है?

#### ■ एस.आर.बोम्मई बनाम भारत संघ मामले की पृष्ठभूमऱ:

- वर्ष 1985 में जनता पार्टी ने कर्नाटक में वधऱनसभा चुनाव जीत कर सरकार बनाई और मुख्ऱमंतरी के रूप में रामकृष्ण हेगड़े को चयनतऱ कयऱ। वर्ष 1988 में हेगड़े के स्थान पर एस.आर.बोम्मई ने मुख्ऱमंतरी का पद ग्रहण कयऱ।
  - सतऱंबर 1988 में जनता दल के एक वधऱयक ने वधऱनसभा के **19 अन्य सदस्यों के साथ पार्टी छोड दी** और बोम्मई के नेतृत्व वाली सरकार से अपना समर्थन वापस ले लयऱ।
- सदस्यों द्वारा दलबदल करने से पार्टी का बहुमत प्रभावतऱ हुआ जसऱके कारण [अनुच्छेद 356 का उपयोग कर राज्ऱ सरकार को बरखास्त कर दयऱ गयऱ](#)। बोम्मई द्वारा बहुमत परीक्षण का अनुरोध कयऱ गयऱ जसऱे [राज्ऱपाल](#) ने अस्वीकार कर दयऱ।
- बोम्मई ने उच्च न्यायालय का रुख कयऱ जसऱमें बोम्मई के वरुद्ध नरऱणय सुनायऱ गयऱ, जसऱके बाद उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की।

#### ■ सर्वोच्च न्यायालय का नरऱणयः

- सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने इस तथ्ऱ पर बल दयऱ कअनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपतऱद्वारा आपात की उदघोषणा का सावधानी से प्रयोग कयऱ जाना चाहयऱ, जैसा कडॉ. बी.आर. अंबेडकर और [सरकारयऱ आयोग](#) द्वारा अनुशंसा की गई थी।
- संसद के दोनों सदनों को [अनुच्छेद 356\(3\)](#) के अनुसार राष्ट्रपतऱद्वारा आपात की उदघोषणा का गहन वशऱलेषण करना चाहयऱ।
  - यदऱ उदघोषणा दोनों सदनों की मंजूरी के बऱना जऱरी की जऱती है तो यह **दो माह के भीतर समाप्त** हो जऱती है और राज्ऱ वधऱनसभा अपना संचालन पुनः प्रारंभ कर सकतऱ है।
- सर्वोच्च न्यायालय उदघोषणा की [न्यायकऱ समीक्षा](#) कर सकतऱ है और इसकी वैधता को चुनौती देने वाली [रटऱ यऱचकऱओं](#) पर वचऱर कर सकतऱ है यदऱ यऱचकऱ में तर्कपूर्ण प्रश्न उठाए गए हैं।
- नरऱणय में यह स्पष्ट कयऱ ककऱसी **राज्ऱ सरकार को बरखास्त करने की राष्ट्रपतऱकी शक्तऱपूर्ण/आतृयंतकऱ नहीं** है अपतऱ सीमाओं के अधीन है।
  - यह माना गयऱ कऱहालॉकअनुच्छेद 356 वधऱनमंडल के वधऱटन को स्पष्ट रूप से संबधतऱ नहीं करता है, फरऱ भी इससे ऐसी शक्तऱयों का अनुमान लगायऱ जा सकतऱ है।
  - [अनुच्छेद 174\(2\)](#) जो राज्ऱपाल को वधऱन सभा को भंग करने की अनुमतऱदऱता है तथा [अनुच्छेद 356\(1\)\(A\)](#), जो राष्ट्रपतऱ को राज्ऱपाल एवं राज्ऱ सरकार की शक्तऱयों को प्रदान करने में सक्षम बनाता है, जो वधऱन मंडल को भंग करने की शक्तऱ प्रदान करता है।

#### ■ एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ मामले का महत्त्वः

- एस.आर. बोम्मई मामला [मुल संरचना सदऱधांत](#) के साथ-साथ [अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को दर्ज करने](#) के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के ऐतऱहासकऱ नरऱणयों में से एक है।

- नरिणय द्वाया अनुच्छेद 356 के दायरे तथा सीमाओं पर स्पष्टता प्रदान की और साथ ही केवल असाधारण परस्थितियों में इसके उपयोग पर ज़ोर दिया ।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नरिधारति सदिधांत सरकारिया आयोग की सफिरशियों के अनुरूप थे ।
- इस मामले ने संघवाद के सदिधांतों की पुष्टि की, जिसमें कहा गया किराज्य सरकारें केंद्र के अधीन नहीं हैं और साथ ही यह सहकारी संघवाद की वकालत भी करती हैं ।
- नरिणय में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति के कार्यों की जाँच करने, संवैधानिक सदिधांतों का पालन सुनिश्चित करने तथा शक्ति के दुरुपयोग को रोकने में न्यायपालिका की भूमिका पर ज़ोर दिया गया ।
- इसने पुष्टि की कविधानसभा का पटल सरकार के बहुमत का परीक्षण करने का एकमात्र अधिकार है, न किराज्यपाल की वयक्तपिरक राय का ।

नोट:

- सरकारिया आयोग ने कुछ मामलों में अनुच्छेद 356(1) को लागू करने से पहले राज्य को सूचित करने की अनुशंसा की ।
  - इसमें कहा गया है कसिमस्या को हल करने के लिये पहले अन्य सभी वकिलपों पर वचार किया जाना चाहिये और साथ ही अनुच्छेद 365 का उपयोग केवल तभी किया जाना चाहिये जब कोई अन्य वकिलप उपलब्ध न हो जो समस्या को हल करने के लिये लागू किया जा सके ।
- सहकारी संघवाद एवं प्रतसिपर्द्धी संघवाद:
  - सहकारी संघवाद में केंद्र तथा राज्य एक कषैतजि संबंध साझा करते हैं, जहाँ वे व्यापक सार्वजनिक हति में "सहयोग" प्रदान करते हैं ।
    - यह राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण एवं कार्यान्वयन में राज्यों की भागीदारी को सक्षम करने हेतु एक महत्त्वपूर्ण उपकरण है ।
    - संघ तथा राज्य संविधान की अनुसूची VII में नरिदष्टि मामलों पर एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिये संवैधानिक रूप से बाध्य हैं ।
  - प्रतसिपर्द्धी संघवाद में केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच संबंध लंबवत एवं राज्य सरकारों के बीच कषैतजि होता है ।
    - प्रतसिपर्द्धी संघवाद में राज्यों को लाभ के लिये आपस में और केंद्र के साथ भी प्रतसिपर्द्धा करने की आवश्यकता होती है ।
    - राज्य धन और नविश आकर्षति करने के लिये एक-दूसरे के साथ प्रतसिपर्द्धा करते हैं, जिससे प्रशासन में दक्षता आती है तथा वकिासात्मक गतिविधियों में वृद्धि होती है ।

## भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 क्या है?

- अनुच्छेद 356 की पृष्ठभूमि:
  - संविधान सभा में प्रारंभिक चर्चा में इस बात पर वचार किया गया किक्या भारत को संघीय या एकात्मक सरकार प्रणाली अपनानी चाहिये ।
    - वचार के दो मत उभरे, जनिमें संघवाद के समर्थक वकिंद्रीकृत शक्तियों के लिये तर्क दे रहे थे और अन्य अधिकि केंद्रीकृत एकात्मक राज्य का समर्थन कर रहे थे ।
  - डॉ. अंबेडकर ने स्पष्ट किया किराज्य संघीय और एकात्मक दोनों सदिधांतों के तहत कार्य करता है, सामान्य परस्थितियों में संघवाद प्रचलति होता है तथा आपात स्थिति के दौरान एकात्मक नयितरण होता है ।
    - दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनियों के बावजूद, परवर्ती सरकारों ने राजनीतिक कारणों से अनुच्छेद 356 को बार-बार लागू किया, जिसके परिणामस्वरूप इसे 132 बार लागू किया गया ।
- अनुच्छेद 356:
  - भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 93 पर आधारति है ।
  - अनुच्छेद 356 के अनुसार, संवैधानिक प्रशासन की वफिलता के आधार पर भारत के किसी भी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है ।
  - राष्ट्रपति शासन दो स्थितियों में लगाया जा सकता है: जब राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त होती है या अन्यथा वह आश्वस्त होता है किराज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर पाती है (अनुच्छेद 356) तथा जब कोई राज्य केंद्र सरकार के नरिदेशों का पालन करने में वफिल रहता है (अनुच्छेद 365) ।
  - राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य सरकार नलिबति हो जाती है और केंद्र सरकार सीधे राज्यपाल के माध्यम से राज्य का प्रशासन चलाती है ।
  - राष्ट्रपति शासन लगाने के लिये संसदीय अनुमोदन आवश्यक है और इसे दो महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से अनुमोदति किया जाना चाहिये ।
  - प्रारंभ में, राष्ट्रपति शासन छह महीने के लिये लागू होता है और इसे हर छह महीने में संसदीय मंजूरी के साथतीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है ।
  - संविधान में 44वें संशोधन (1978) ने राष्ट्रपति शासन को एक वर्ष से अधिक बढ़ाने पर प्रतर्बिध लगा दिया, जिससे केवल राष्ट्रीय आपातकाल के मामले में वसितार की अनुमति मिलति है या यदिरिवाचन आयोग राज्य विधानसभा चुनाव आयोजति करने में कठिनाइयों के कारण आवश्यकता को प्रामाणित करता है ।
- केंद्र-राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग (1988) की रिपोर्ट के आधार पर, बमर्म्ई मामले, 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने उन स्थितियों को सूचीबद्ध किया जहाँ अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का प्रयोग उचित या अनुचित हो सकता है ।

| अनुच्छेद 356 का उचित उपयोग                                                                                              | अनुच्छेद 356 का अनुचित उपयोग                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| त्रिशंकु अधिनियम: चुनाव के बाद किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता।                                                      | वैकल्पिक मंत्रालय गठन की खोज किये बिना मंत्रिमंडलों ने त्याग-पत्र दे दिया। |
| बहुमत दल ने मंत्रालय बनाने से इनकार कर दिया, और बहुमत वाला कोई गठबंधन मंत्रालय उपलब्ध नहीं है।                          | राज्यपाल ने बहुमत परीक्षण की अनुमति दिये बिना राष्ट्रपति शासन लगा दिया।    |
| अधिनियम में हार के बाद मंत्रिमंडल ने त्याग-पत्र दे देता है और कोई भी पार्टी बहुमत के साथ नया मंत्रालय नहीं बना सकती है। | लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी पार्टी की बड़ी हार हुई है।                      |
| संवधान का आंतरिक तोड़फोड़ या जानबूझकर उल्लंघन।                                                                          | आंतरिक अशांति तोड़फोड़ या विधितन की श्रेणी में नहीं आती।                   |
| राज्य सरकार केंद्र सरकार के संवैधानिक निर्देश की अवहेलना करती है।                                                       | उचित चेतावनी के बिना कुप्रशासन या भ्रष्टाचार के आरोप।                      |
| शारीरिक विच्छेद, राज्य सुरक्षा को खतरे में डालना।                                                                       | अंतरपक्षीय मुद्दों या अपरासंगिक उद्देश्यों के लिये दुरुपयोग।               |
|                                                                                                                         | आपातकालीन स्थिति को छोड़कर राज्य सरकार को पूर्व चेतावनी नहीं दी जाती है।   |

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के नमिनलखिति में से कौन-से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? (2017)

1. राज्य अधिनियम का विधितन
2. राज्य के मंत्रपरिषद् का हटाया जाना
3. स्थानीय निकायों का विधितन

नीचे दिये गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

**[?/?/?/?/?]:**

प्रश्न. यद्यपि परिसंघीय सिद्धांत हमारे संविधान में प्रबल है और वह सिद्धांत संविधान के आधारित अभिलक्षणों में से एक है, परंतु यह भी इतना ही सत्य है कि भारतीय संविधान के अधीन परसिंघवाद सशक्त केंद्र के पक्ष में झुका हुआ है, यह एक ऐसा लक्षण है जो प्रबल परसिंघवाद की संकल्पना के विरोध में है। चर्चा कीजिये। (2014)